

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा
अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 07 जनवरी, 2008

विषय:- अपर महाधिवक्ता को अनुमन्य फीस में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 126-एक(6)/छत्तीस(1)/न्या. अनु./2005 दिनांक 12 सितम्बर, 2005 एवं अपर महाधिवक्ता को अनुमन्य फीस का स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या 241/XXXVI/ (1)/2006 दिनांक 13 जुलाई, 2006 को अधिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल मा0 उच्चतम न्यायालय, दिल्ली हेतु आवद्ध किये जाने वाले अपर महाधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दरों पर फीस दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) रिटेंर फीस नियत — रु0 15,000 प्रतिमाह (रुपये पन्द्रह हजार मात्र प्रति माह)
- (2) पुस्तकालय भत्ता — रु0 1,500 प्रतिमाह (रुपये एक हजार पांच सौ मात्र प्रतिमाह)
- (3) मा0 उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु — रु0 10,000 प्रति कार्य दिवस (रुपये दस हजार प्रतिकार्य दिवस)
अनुमन्य फीस (चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक अनुदान संख्या 04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार परामर्शदाता

(काउंसिल)-00-03-महाधिवक्ता-00-16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1200/वित्त अनुभाग-5/2008 दिनांक 07 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव, न्याय

संख्या: 07(1)/XXXVI/ (एक)2008 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून ।
- 2- कोषाधिकारी देहरादून ।
- 3- श्री अरुणेंद्र चौहान, विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
- 4- सुश्री रचना श्रीवास्तव, अपर महाधिवक्ता (उत्तराखण्ड), 139 न्यू लायर्स चैम्बर्स, भगवानदास रोड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
- 5- इरला बैंक अनुभाग ।
- 6- वित्त अनुभाग-5 ।
- 7- निर्देशक एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 8- विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(कै० पी० पाटनी)
अनुसचिव ।